भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4446

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

ओडिशा में शहरी विकास और आवास योजनाएँ

4446. श्री अनन्त नायकः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा में शहरी विकास और आवास योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है;

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) और अन्य शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत क्योंझर जिले में जनजातीय समुदायों को कितना लाभ प्रदान किया गया है;

(ग) ओडिशा में अमृत और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या कितनी है और क्योंझर जिले में उक्त योजनाओं के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(घ) ओडिशा में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), जल प्रबंधन, सीवरेज प्रणाली और स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत आवंटित कुल धनराशि और इन योजनाओं के अंतर्गत क्योंझर जिले में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का क्योंझर जिले में जनजातीय समुदायों के लिए कोई विशेष आवास और अवसंरचना योजना लागू करने का विचार है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): सातवीं और बारहवीं अनुसूची के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमयूवाई-यू और पीएमयूवाई-यू 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0) आदि के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इन मिशनों के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता (सीए) जारी की जाती है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत, ओडिशा में प्रारंभ से अब तक 2,03,380 आवासों को

स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1,84,643 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 1,58,659 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ख) और (ड.): ओडिशा के क्योंझर जिले में, जनजातीय समुदायों के लिए पीएमएवाई-यू के तहत 2797 आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से शुरुआत से 2526 आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ऋण सम्बद्ध सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता करना है, ताकि पात्र लाभार्थियों के लिए किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और उन्हें किराये पर लिया जा सके।

(ग) और (घ): अमृत: ओडिशा में, 9 शहर अर्थात्; बालेश्वर टाउन, बारीपदा टाउन, भद्रक, भुवनेश्वर टाउन, ब्रह्मपुर , कटक, पुरी, राउरकेला टाउन और संबलपुर टाउन अमृत के अंतर्गत शामिल हैं। ओडिशा में अमृत के तहत 191 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसके लिए 1,714.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1,535.57 करोड़ रुपए की 130 जलापूर्ति परियोजनाएँ और 138.21 करोड़ रुपए की 13 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत, ओडिशा में 3,756.57 करोड़ रुपए की 211 जलापूर्ति परियोजनाएँ और 184.31 करोड़ रुपए की 137 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। अमृत और अमृत 2.0 के तहत क्योंझर जिले में किसी भी शहर को अनुमोदन नहीं दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत, 796.97 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से से 785.23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,373 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से से 524.04 करोड़ रुपए जारी/स्वीकृत किए गए हैं।

एसबीएम -यू: एसबीएम-यू को ओडिशा के क्योंझर जिले सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया गया है, ताकि आदिवासी समुदायों सहित सभी नागरिकों के लिए शहरों में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सके। निधियाँ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित/जारी की जाती हैं, न कि जिलों को। ओडिशा को आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

आवंटित निधियाँ		**जारी की गई निधि**	
एसबीएम-यू	**एसबीएम-यू 2.0**	**एसबीएम-यू**	**एसबीएम-यू 2.0**

(2014-2021)	(2021-2026)	(2014-2021)	(2021-2026)
372.02	821.40	288.84	205.92

एसबीएम-यू के अंतर्गत, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) की 1,65,925 यूनिट और 12,211 लाख सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) का निर्माण किया गया है। कुल 2,038 वार्डों में से, 2,037 वार्ड घर-घर जाकर कलेक्शन कर रहे हैं और 2,030 वार्ड स्रोत पृथक्करण कर रहे हैं। प्रतिदिन 1,823 टन (टीपीडी) अपशिष्ट में से 1,759 टीपीडी अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम): ओडिशा राज्य में एससीएम के तहत भुवनेश्वर और राउरकेला चुने गए थे। कुल 988 करोड़ रुपये यानी राउरकेला स्मार्ट सिटी और भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी के लिए क्रमशः 490 करोड़ रुपये और 498 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) का दावा किया गया है। जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में, 498 करोड़ रुपये की सभी 9 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, क्योंझर जिला एससीएम के अंतर्गत शामिल नहीं है।

***